प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक – 23 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 06 – 13 जून 2016 मूल्य पांच रूपए

सरकार के अपने बागवानी, एपीएमसी और ट्रांसपोर्ट विभागों ने भी नही किया वीरभद्र के दावों का समर्थन

शिमला/शैल। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई और ईडी एक साथ जांच झेल रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिह से सीबीआई ने दो दिन करीब पन्द्रह घन्टे विस्तृत पूछताछ की है। लेकिन इस पुछताछ के बाद ऐजैन्सी के सूत्रों से जो जानकारी बाहर आयी है उसके मुताबिक वीरभद्र सिंह अपने जबाव से सीबीआई को सन्तुष्ट नही कर पाये हैं। वीरभद्र ने भी इस पूछताछ पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया जारी नही की है। जबकि वह अब तक इस सबके लिये प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर और अरूण जेटली को लगातार कोसते हुए यह दावा करत रहे हैं कि वह पाक साफ हैं। वीरभद्र की छवि के विपरीत सीबीआई का सन्तुष्ट न होना स्वाभाविक रूप से यह सवाल खड़े करता है कि जांच ऐजैन्सी के पास ऐसे क्या तथ्य हैं जिन पर मुख्यमन्त्री संतोषजनक जबाव नही दे पाये है। इसे समझने के लिये पूरे मामले की बुनियाद और उस पर आयी जांच ऐजैन्सी की रिपोर्ट को समझना आवश्यक है। क्योंकि इसी रिपोर्ट को देखकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच का आधार बने दस्तावेज देने तथा अटैचमेन्ट आदेश को रद्द करने से इन्कार कर दिया है।

स्मरणीय है कि इस प्रकरण में पहली शिकायत प्रंशात भूषण ने उस समय की थी जब मित्तल इस्पात उद्योग समूह के मुख्यालय में दिसम्बर 2010 में हुई छापामारी के दौरान पकड़ी गयी सीएमडी की डायरी में कुछ सांकेतिक नामों के आगे मोटी रकमें लिखी मिली थी। इन सांकेतिक नामों में एक नाम वी बी एस था । इस नाम के मीडिया में उछलने पर वीरभद्र सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी करते हुए जारी करते हुए इसे पेड न्यूज करार देते हुए चुनाव आयोग तक में शिकायत दर्ज करवाते हुए इसके पीछे अनुराग ठाकुर और अरूण जेटली के होने का आरोप लगाया था। इस पृष्ठभूमि में आगे बढ़े इस मामले में सबसे पहले आयकर विभाग ने जांच की। आयकर की जांच का आधार एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान के बैंक खातों में भारी कैश जमा होना तथा उस पैसे का जीवन बीमा पालिसीयां खरीदने में निवेश किया जाना बना था। जब आयकर ने आनन्द चौहान को लेकर जांच शुरू की तो प्रारम्भ में 22 – 11 – 2011 को उसने इस पैसे को अपने परिवार का पैसा बताया लेकिन बाद इसे वीरभद्र के सेब बागीचे की आय तथा अपने को बागीचे का प्रबन्धक बताते हुए इस आश्य का वीरभद्र सिंह के साथ 15 – 6 – 2008 को हस्ताक्षरित एक एमओयू की फोटो कापी भी पेश कर दी । यह एमओयू आने से पूरे मामले का आकार प्रकार ही बदल गया। इसे बागीचे की आय प्रमाणित करने के लिये 2 – 3 – 2012 को वीरभद्र ने तीन वर्षो की आयकर रिटर्नज संशोधित कर दी। इस संशोधन में तीन वर्षो की मूल आय 47.35 लाख को बढ़ाकर 6.56 करोड़ दिखाया गया।

इस पर जीवन बीमा पालिसीयों का पूरा ब्योरा एलआईसी की संजौली ब्रांच से तलब किया गया। पेश किये गये एमओयू के स्टांप पेपर की जांच की गयी। सेब परवाणु के व्यापारी चुन्नी लाल को बेचा बताया गया इसके लिये चुन्नी लाल भी जांच के दायरे में आ गया। इतने सेब की ढुलाई के लिये जो वाहन प्रयोग में लाये गये उनकी प्रमाणिकता के लिये परिवहन विभाग से रिपोर्ट ली गयी। सेब की ढुलाई में लगे वाहनों की एन्ट्री एपीएमसी के रिकार्ड में भी दर्ज होती है। इस पर एपीएमसी से रिपोर्ट ली गयी है। वीरभद्र का बागीचा 105 बीघे का है और इसमें 3500 पेड़ होने तथा उनसे 35000 वाक्स के उत्तपादन का दावा किया गया है। इस दावे की प्रमाणिकता के लिये निदेशक उद्यान विभाग से रिपोर्ट ली गयी है। इस तरह एलआईसी, स्टांप पेपर विक्रेता और नासिक की सिक्योरिटी प्रैस उद्यान विभाग, एपीएमसी और परिवहन विभाग आदि से जो रिपोर्ट मिली है उससे वीरभद्र, आनन्द चौहान और चुन्नी लाल के इस बारे में सारे दावे आधारहीन प्रमाणित होते हैं और संभवत: इसी कारण सीबीआई वीरभद्र के जबाव से सन्तुष्ट नही है।सीबीआई की जांच की अवधि मूलत: 28 – 05 – 2009 से 26 – 6 – 2012 के बीच की रही है और इसी अवधि में वीरभद्र केन्द्र में मन्त्री थे।

वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्य आनन्द चौहान के माध्यम से जीवन बीमा पालिसीयां ले चुके है यह उनका रिकार्ड है। इन पालिसीयों के लिये आनन्द चौहान ने अपने बैंक खातों के अतिरिक्त एक कनुप्रिया राठौर और मेघराज शर्मा के खातों का भी इस्तेमाल किया है। बागीचे के प्रबन्धन के 15 – 6 – 2008 और 17 – 6 – 2008 को दो एमओयू सामने आये हैं। 15 – 6 – 2008 को आनन्द चौहान और वीरभद्र के बीच एमओयू साईन होता है। लेकिन 17 – 6 – 2008 को विश्म्बरदास के साथ वीरभद्र के मैनेजर राम आसरे यह एग्रीमेन्ट साईन करते हैं। इनमें इस्तेमाल हुए स्टांप पेपरों पर कंटिग और ओवर राईटिंग है और मूलत: यह एक लायक राय के नाम हैं जो इन्हें यूको बैंक कोटखाई में पेश करता है।जिस तारीख को यह एमओयू साईन होते हैं उस तारीख को यह स्टांप पेपर नासिक प्रैस में हैं। आनन्द चौहान के खातों में सारा पैसा कैश जमा होता है। मई 2010 में चुन्नी लाल आनन्द चौहान का एक करोड़ की कैश एंडवांस पेमैन्ट करता है जांच में वह पैसा उसी के कार्यालय में अलग – अलग 13 फर्मो द्वारा दिया जाना बताता है लेकिन जांच में यह फर्में और पेमैन्ट प्रमाणित नही होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जीवन बीमा की सारी पालिसीयां 2007 से 2010 के बीचे ली गयी हैं विक्रमादात्यि के नाम भी इसी अवधि में कराड़ो की पालिसीयां हैं लेकिन जांच में यह सामने आया है कि 2010 तक विक्रमादात्यि ने कभी आयकर रिटर्न नही भरी है उसने 2011 से रिटर्न भरना शुरू किया है। जबकि विक्रमादित्य के नाम पर 31 – 12 – 2010 को बीमा पालिसी तथा एफडीआर हैं। विक्रमादित्य के इस पैसे स्त्रोत क्या है यह सवाल विक्रमादित्य और वीरभद्र सिंह दोनो के लिये कठिन है।

सीबीआई सूत्रों की माने तो अब इस मामले में प्रतिभा सिंह, आनन्द चौहान और चुन्नी लाल से पूछताछ की जायेगी। यह भी माना जा रहा है कि कुछ संपत्तियां विदेश में भी होने का सन्देह है और उसमें कुछ निकटस्थ रिश्तेदारों के नाम भी सामने आये हैं। इन लोगों से भी पूछताछ की तैयारी है वीरभद्र सिंह से अब ईडी पूछताछ करेगी और उसमें वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर को लेकर भी सवाल आयेगें।

(जांच रिपोर्ट के अंश पृष्ठ 8 पर पढ़े)

नेतृत्व परिवर्तन की संभानाए फिर चर्चा में

शिमला/शैल। प्रदेश में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की संभानाओं पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस बार इन चर्चाओं को परिवहन मन्त्री जी एस बाली को केन्द्रिय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के भाजपा में शामिल होने के लिये आये खुले निमन्त्रण ने जन्म दिया है। मजे की बात यह है कि इस निमन्त्रण पर बाली ने भी कोई प्रतिक्रिया नही दी है। कुछ दिनों से बाली और वीरभद्र के रिश्तों को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। इन्ही चर्चाओं के बीच स्वास्थ्य मन्त्री ठाकुर कौल सिंह के विक्रमादित्य के प्रति आये बदलाव ने भी कई हल्कों में कई अटकलों को जन्म दे दिया है। यह संयोग है कि इन अटकलों के संकेत उभरने के बाद ही सीबीआई ने वीरभद्र सिंह से पूछताछ का दौर शुरू किया है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ के दौर के शुरू होने के बाद शीघ्र ही इस संद्धर्भ में चालान अदालत में दायर होने की संभावना भी बढ़ जायेगी। जून के अन्त तक सीबीआई और ईडी की जांच प्रक्रिया भी पूरी हो जाने की उम्मीद है।

सीबीआई और ईडी की जांच में अब तक जो कुछ सामने आ चुका है। उसके बाद यह तय है कि इन जांचों के अन्तिम परिणाम स्वरूप जो चालान अदालत में जायेगे उनपर चार्ज लगने की संभावनाएं पक्की हैं। चार्ज लगने के बाद कांग्रेस हाईकमान और स्वयं वीरभद्र पर भी नेतृत्व में बदलाव के लिये दवाब बढ़ जायेगा। यह वह स्थिति होगी जिसमें कांग्रेस विधायक दल के अन्दर भी हर रोज समीकरण बनने और बदलने शुरू हो जायेगे। वीरभद्र इस स्थिति में यदि विधानसभा भंग करवाकर समय से पहले ही चुनाव करवाने का प्रस्ताव रखेंगे तो शायद उनके प्रस्ताव को पूरा समर्थन नहीं मिल पायेगा। क्योंकि वीरभद्र के पास अब ऐसी ऐज और स्टेज नही बची है जिसमें एक बार फिर उनसे नेतृत्व की उम्मीद की जा सके। राजनीतिक विश्लेषक और सीबीआई तथा ईडी में चल रहे मामलों पर पैनी नजर रखने वाले आश्वस्त हैं कि अब इस प्रकरण में वीरभद्र और उनके सलाहकार जिस तरह की गल्तीयां कर चूके हैं उनको सामने रखते हुए उनके बच निकलने के रास्ते लगभग बन्द हो चुके हैं। जानकार मानते हैं ईडी मामलें में पूरे परिवार के साथ कुछ अन्य संबधियों के लिये भी कठिनाई खड़ी हो सकती है।

विश्लेषकों का मानना है किइस बार वीरभद्र की विजिलैन्स उनको वाच्छित परिणाम नहीं दे पायी है क्योंकि जिस स्तर पर धूमल के खिलाफ कारवाई शुरू की गयी थी उसके इस संद्धर्भ में अब तक ठोस परिणाम सामने आ जाने चाहिए थे। लेकिन इन मामलों में करोडों रूपये वकीलों को फीस देने के बाद भी परिणाम का शून्य रहना पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसमें भी सबसे हैरत वाली बात तो यह है कि वीरभद्र इन मामलों पर जितने ब्यान और दावे दागते रहे हैं उस अनुपात में उनकी नाक के नीचे जो कुछ पकता रहा उसे वह समझना तो दूर सूंघ भी नही पाये। जब सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ मामले बनाये थे उन्हें तभी ही मुख्यमन्त्री की कुर्सी छोड़कर पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए थी। क्योंकि इन मामलों में कहां क्या चूक हो चुकी है। इसके बारे में उनसे ज्यादा और कोई नही समझ सकता था। बल्कि इस मामले में जिस तरह से परिवार के सदस्यों की भूमिका सामने आ रही है उसे देखते हुए यह लगता है कि इन लोगों में भी राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी रही है। क्योंकि सलाहकारों के तो अपने अपने स्वार्थ थे जो कि वीरभद्र के सत्ता में रहने से ही पूरे होने थे। यदि उस समय मुख्यमन्त्री पद को छोड़कर पार्टी की अध्यक्षता संभाली होती तो उस समय राज्यसभा में जाने से भी कोई रोक नही पाता । राज्यसभा में छ: वर्ष का कार्यकाल मिल जाता और इस अवधि में परिवार को भी प्रदेश की राजनीति में स्थापित कर पाते।लेकिन आज वीरभद्र के हाथ से यह सारे विकल्प निकल चुके हैं। अब केवल यह देखना वाकी है कि वह बदली परिस्थितियों में किस तरह का कदम उठाते हैं।

लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अब नेतृत्व परिवर्तन के सवाल को ज्यादा समय तक टाला नही जा सकेगा।

शहीदों के जीवन से प्रेरणा लें–राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हमारे देश का शानदार इतिहास है, जहां अनेक वीर योद्धाओं ने देश की एकता एवं अखंडता के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अपने प्राणों को न्योच्छावर किया है, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंदा सिंह बहादुर उनमें से एक था, जिन्होंने सिक्ख साम्राज्य की स्थापना की और सर्वस्व कुर्बान कर भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व के लिए तथा गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी के रूप में हिन्दू व सिक्ख दोनों ही उनका सम्मान करते थे। उन्होंने लोगों से शहीदों के आदर्शों का अनुसरण करने का आग्रह किया।

राज्यपाल गेयटी थियेटर शिमला में बंदा सिंह बहादुर जी के 300वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा बंदा सिंह बहादुर ने सच्चाई एवं न्याय के लिए तत्कालीन शासकों की क्रूरता के विरूद्ध अनेक लड़ाईयां लड़ी। उन्होंने कहा कि बंदा सिंह बहादुर को मुगल राज्य में बंदी बनाकर उनकी परिवार सहित निर्मम हत्या कर दी थी। उन्होंने देश और धर्म के लिए तथा उस समय समाज में व्याप्त बुराईयों के प्रति लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि बंदा बहादुर धर्म के लिए जिए और हमें इस महान् विभूति के जीवन से धर्म के संरक्षण की शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी इस महान आत्मा के

बलिदान की कहानियों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के समारोह युवा पीढ़ी में बाबा बंदा सिंह बहादुर जैसे हमारे शूरवीरों के महान् योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में मद्दगार होते हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की कि आधुनिक समय में युवाओं को बाबा बंदा सिंह बहादुर जैसे योद्धाओं द्वारा देश के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान के बारे में बहुत कम जानकारी है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि एक समय था कि जब हम आर्थिक एवं आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत थे, लेकिन हमें उन कारणों को समझने की आवश्यकता है, जिससे हमारा देश गुलाम हुआ। उन्होंने कहा कि एकजुटता, एकरूपता, राष्ट्र भक्ति एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को मजबूत कर हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ सकता है।

उन्होंने बाबा बंदा बहादुर द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए आयोजकों को बधाई दी और लोगों से उनके द्वारा दिखाए गये भाइचारे, शांति तथा सम्पन्नता के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि समृद्ध विरासत एवं हमारे शानदार अतीत के संरक्षण के लिए हमें विशेष प्रयास करने चाहिए। उन्होंने युवाओं से शहीदों एवं महान व्यक्तियों की आत्म कथाओं से जुड़ी पुस्तकें पढ़ने को कहा, जो उन्हें प्रेरणा देंगीं।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने 'हिमालय ध्वनि' पत्रिका के 25 वर्ष पूर्ण होने पर इसके विशेष अंक जारी किया। उन्होंने इस अवसर पर सम्बंधित क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए महान विभूतियों को सम्मानित भी किया। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने कहा कि बंदा बहादुर ने मुगलों के विरूद्ध आंदोलन चलाया तथा देश व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने बंदा बहादुर की शिक्षाओं एवं संदेश के अनुसरण की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर पंजाब खाद्दी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि बाबा बहादुर एक महान प्रशासक थे, जिन्होंने मुगल राज्य में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और वास्तविक रूप से खेती करने वालों को भूमि के मालिक बनाया।

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. प्रेम शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। वीएचपी के राज्याध्यक्ष अमन पुरी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

विधायक सुरेश भारद्वाज, हि.प्र. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ए.डी. एन. वाजपेयी, पूर्व आयुक्त जे.एस. राणा, पत्रिका की सहायक सम्पादक रजनी ठुकराल, गुरु सिंह सभा के प्रधान इन्द्रजीत सिंह, राजपूत सभा के प्रतिनिधि शैलेन्द्र वर्मा, वीएचपी के संगठन सचिव मनोज कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

तम्बाकू के सेवन पर अंकुश के लिये एकजुट प्रयासों की आवश्यकता:कौल सिंह

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि समाज से नशा विशेषकर तम्बाकूयुक्त उत्पादों के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिये सभी का सहयोग एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

ठाकुर चण्डीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर आयोजित ऑरियन्टेशन एवं कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला के समापन अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न सात राज्यों–हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्ड, जम्मू–कश्मीर तथा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विश्व में तम्बाकू उत्पादों के सेवन से सर्वाधिक मौतें होती हैं और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी राज्य तम्बाकू से अछूता एवं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हम सभी पर यह जिम्मेवारी आ गई है कि हम इसके निदान के लिए ठोस रणनीति तैयार करें और इसका संबंधित राज्यों में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएं तथा इसे व्यावहारिक रूप दें।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
" INVITATION FOR BIDS(IFB) "

The Executive Engineer Shimla Division No. I HP PWD Shimla-3 on behalf of Governor of HP invites the online bids on item rate. In Electronic tendering system in-2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost Rs	EMD	Cost of Tender	Time Allowed
1.	Widening & Improvement of Shoghi Mehli Junga Sadhupul road km 12/375 to 48/925 (SH:- C/O RCC Slab Culvert at RD 33/700)	1732451/-	33487/-	500/-	60days
2.	C/o parking facility for GAD vehicle (SH:- C/O M.S steel parking at kasumpti near jai Bhawan)	1463253/-	29300/-	500/-	60 days.

Availability of Bid Document and mode of submission : The bid document is available online and bid should be submitted in online onmode on website http://hptenders.gov.in.
Bidder would be register in the web-site which is free of cost .For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA) " "Aspiring bidders ho have not obtained there ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://hptenders.govt.in. in /digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Dates:-

1. Date of Online Publication :	17.06.2016 up to 18:00 HRS
2. Document Download Start and End Date .	17.06.2016. 18:00 HRS up to 04.06.2016 16:00 HRS.
3. Bid Submission Start and End Date	17.06.2016 . 18:00 HRS. up to 04.06.2016.16:00HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document.	05.07.2016 upto 10:30 HRS.
5. Date of opening of Technical Bid	05.07.2016 11:00 HRS
6. Date of opening, of Financial Bid.	05.07.2016 11:00 HRS

4.Tender Details:-
The Tenders documents shall be uploaded online in 2 cover.
i) Cover -1:- Shall contain scanned copies of all " Technical Documents/eligible Information"
ii) Cover-2:- Shall contain. BOQ/Financial Bid where contractor will quote his offer for each item.
5. **SUBMISSION OF ORGINIAL DOCUMENTS:-**The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the O/o Executive Engineer Shimla Division No. I H.PPWDShimla - 3. as specified in Key dates Sr .No. 4 on Tender Opening Date. Failing which the bid will be declared non-responsive.
6. **BID OPENING DETAILS:** The bids shall be opened on 05.07.20156at 11:30 HRS in the office. In the office of Executive Engineer Shimla HP PWD. Shimla - HP by the authorised officer. In their interest the tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids a specified ,the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days .after the deadline date for bid submission.
8. Other details can be seen in the biding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control .Even thought the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-0935/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
" INVITATION FOR BIDS(IFB) "

1.**The Executive Engineer HPPWD Division Fatehpur Distt. Kangra H.P.** on behalf of the Governor of HP invites the online bids on item rate in elect0ronic tendering system. In 2 cover system for the under mentioned buirling works from the eligible and approved contractors/firms registered with HPPWD Department .

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost Rs	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender	Eligible Class of Contractor
1.	Construction of sunhara Khadloh Nangal Road km 4/0 to 8/860 Under SCSP (SH:- Providing and Laying 20mm thick premix carpet surfacing including (IRC type -B) seal coat at R.D. 4/0 to 5/810)	1228864/-	24600/-	One Month	500/-	Class D
2.	Construction of Chandbeh Dhaniayana Bhulana -Mandlai -Kanal-Banchareti Via- Dial in km 0/0 to 4/0from MTN Road side & 11/500 to 13/0 from Ban Chareti side (Total Lenth 5.5 km (SH:- Providing and Laying Grading -I 90 mm to 45mm size at RD 2/900 to 3/650, Grading -II 63 mm to 45mm size and 20mm thick premix carpet surfacing including (IRC type -B) seal coat in km 2/650 to 3/650)s .	1145012/-	22900/-	One Month	500/-	Class D
3.	Construction of Hadal Bari Barla Road km 0/0 to 5/0 Under SCSP (SH:- Providing and Laying Grading -II 63mm to 45mm size and 20mm thick premix carpet surfacing including (IRC type -B) seal coat in km 2/0 to 3/50s0)	1359913/-	27200/-	One Month	500/-	Class D
4.	Construction of sunhara Khadlow Nangal Road km 4/0 to 8/860 Under SCSP (SH:- Construction of Retaining wall at RD. 0/010 to 0/022 B/ 2/725 to 2/795 to 2/805, 3/025 to 3/035)	1120713/-	22450/-	Two Months	500/-	Class D

Date of Online Publication is 22.06.2016 at 1::00 HRS Document /bid download start and end date are 22.06.2016 at 10:30 hrs to 11.07.2016 upto 1700 hrs. Bids will be opened on 12.07.2016 at 11:00 hrs The tender forms and other detailed conditions can be obtained from the website **www.hptends.gov.in**

Adv. No.-0984/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITIGN TENDER

Sealed item rates tenders on forms No. 6&8 are by hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of H.P for the following works from registered PWD contractors. The tenders should reach this office on or before 04.07.2016 upto 10:30 AM and shall be opened on the same day at 11:00AM in the presence of tenders or their authorized reprsenentative ho wish to be present. The telegraphic and conditional tenders shall not be accepted. The tender forms can be from this office against cash payment (Non -fundable) upto 02.07.2016 till 3:00PM.

The Earnest Money in the Shape of National Saving Certificate /time deposit /saving account in any of the post office saving bank account in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer Mechanical Division HP PWD Kulu must accompany each tender. The tender received without proper earnest money will summarily be rejected. The undersigned reserve the right to received without assigning any reasons. If holiday falls on date of opening of tender it will be opened on next woking day.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost Rs	Cost of Tender Form	Earnest Money	Time Limit
1.	Construction of material Ropway from Raish Nallah to village Batadhar in G.P Bhandi Sub tehsil Aut Distt Mandi (HP) (SH:- Manufacturing, supplying & stacking of parts and equipment stage)	3,65.821/-	350/-	7,350/-	Two Months
2.	Construction of 130 Rmt railing near Khalara Nallah tehsil & Distt Kullu (HP)	2,29,836/-	350/-	4,600/-	Two Months
3.	Special repair estimate of 16.50 mtrs span motorable bridge at Nagu jhor in lug valley Distt. Kullu (HP)	5,30,832/-	350/-	10,650/-	Two Month

TERMS AND CONDTIONS:
1Copy of Latest renewal /enlistment, sale Tax number and proof of dealing in steel items must also accompany with application for purchase of tender form for item No. I
2. The rate shall be valid upto 120 days.
3.Sale Tax @2 % Income Tax @ 3% Surcharge @ 10 % & 3% Education cess on income tax ill also be deducted from the bill.
4. Conditional /telegraphic tenders are not acceptable.
5 Tenders received after due date and time shall not be entertained.

Adv. No.-0989/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति वचनबद्धः मुख्यमंत्री

विश्व पर्यावरण दिवस प्रदेश में दो राष्ट्रीय पार्क, तीस वन्य जीव सेंचुरी और तीन कंजरवेशन रिजर्व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए रैली आयोजित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार समृद्ध जैव संसाधनों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है, जो राज्य की बहुमूल्य निधि व परिसम्पत्ति है और प्रदेश सरकार विकास गतिविधियों के लिए पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर कभी समझौता नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के सभागार में राज्य विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इस वर्ष के कार्यक्रम का थीम 'गो वाईल्ड फॉर लाईफ:जीरो टॉलरेंस फॉर द इललीगल वाईल्डलाईफ ट्रेड' मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस का 'थीम' हमें विलुप्ती की कगार पर उन सभी प्रजातियां के संरक्षण व उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के प्रति लोगों को सचेत करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन हमें अपने आप व अन्य को पर्यावरण के महत्व को याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दो राष्ट्रीय पार्कों, तीस वन्य जीव सेंचुरी तथा तीन कंजरवेशन रिजर्व स्थापित किए हैं।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अवैध वन्य प्राणी व्यापार के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकें। उन्होंने इस गैर कानूनी व्यापार से पर्यावरण, आर्थिकी, समुदाय व सुरक्षा को होने वाले नुकसान को समझने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आदतों व रूचियों में बदलाव लाना होगा ताकि वन्य जीव उत्पादों की मांग कम हो सके। उन्होंने कहा कि हालांकि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयासों से कुछ प्रजातियों के संरक्षण में सफलता मिली है, परन्तु फिर भी बहुत सी प्रजातियां अन्तर्राष्ट्रीय अभियानों के बावजूद विलुप्त होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव उत्पादों के बढ़ते व्यापार से बहुमूल्य जैव विविधता व प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा है और बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का किफायती से उपयोग करना चाहिए ताकि इन्हें भविष्य की पीढ़ियों की समृद्धि के लिए सरक्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण के सरंक्षण के लिए अपनी सेवाएं देने का आहवान किया। उन्होंने इस अवसर पर वन्य जैव संसाधनों के संरक्षण के लिए 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत का संकल्प लेने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहर में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए।

इस अवसर पर परिषद के सहयोग से लगभग 40 स्कूलों के 700 विद्यार्थियों द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली गई।

राष्ट्रपति की कल्याणी हैलीपेड पर गरिमापूर्ण विदाई

शिमला/शैल। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके शिमला में पांच दिनों के प्रवास के उपरान्त कल्याणी हैलीपेड पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गरिमापूर्ण विदाई दी।

स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा, नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान, उप-महापौर टिकेन्द्र पंवर, मुख्य सचिव वी.सी. फारका, पुलिस महानिदेशक संजय कुमार, जीओसी-इन-सी आरट्रेक ले. जनरल पी.एम. हारिज, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा सिविल, पुलिस व सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी अन्यों सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।

कौल सिंह ठाकुर भारत ज्योति पुरस्कार से सम्मानित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्र स्तरीय भारत ज्योति पुरस्कार से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें यहां इंडिया इंटरनेशनल फ्रैण्डशिप सोसायटी द्वारा आर्थिक विकास व राष्ट्रीय एकता पर आयोजित सेमिनार में प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि कौल सिंह ठाकुर गत 43 वर्षों से राजनैतिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किये हैं जिसके लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने फ्रैण्डशिप सोसायटी का आभार व्यक्त किया कि संस्था विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले लोगों को समय-समय पर सम्मानित करती रहती है। उन्होंने कहा कि उनका राजनैतिक सफर साफ-सुथरा रहा है और इस दौरान प्रदेश की सेवा करने का जो अवसर उन्हें मिला है उसके लिए वह हिमाचलवासियों के कृतज्ञ हैं।

इससे पूर्व फ्रैण्डशिप सोसायटी के महासचिव गुरप्रीत सिंह ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे जिनमे शिवराज पाटिल, पूर्व लोकसभा स्पीकर, भीष्म नारायण सिंह, पूर्व राज्यपाल, जे.बी.जी. कृष्णामूर्ति, पूर्व चीफ चुनाव आयुक्त, सरदार जोगिन्द्र सिंह, पूर्व निदेशक सी.बी.आई. प्रमुख थे।

लाहौल उपमण्डल में पांच पंचायतें चुनी गयी निर्विरोध

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के उप- चुनाव में नामांकन वापिस लेने की समयवधि समाप्त होने के उपरान्त इन चुनावों में भाग ले रहे अभ्यार्थियों की तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। पूरे प्रदेश में जिला परिषद सदस्यों के 2 पदों, पंचायत समिति सदस्यों के 5 पदों, पंचायत प्रधानों के 8 पदों तथा उप-प्रधानों के 5 पदों के अतिरिक्त पंचायत सदस्यों के 183 पदों के लिए उप-चुनाव करवाया जा रहा है। शहरी निकायों में 23 सदस्यों के पदों के लिए उप-चुनाव किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्यों के दो पदों में कांगड़ा तथा बिलासपुर जिला में एक-एक वार्ड के लिए उप-चुनाव हो रहा है तथा इन दोनों वार्डों से चार-चार उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कांगड़ा, बिलासपुर तथा कुल्लू जिले में पंचायत समितियों के 5 वार्डों के लिए 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि लाहौल में पंचायत समिति के 15 वार्डों के लिए 48 उम्मीदवार उप-चुनाव में भाग ले रहे हैं, जबकि 28 पंचायतों में प्रधान पद के लिए 74, उप-प्रधान पद के लिए 62 तथा 140 वार्ड सदस्य के पदों के लिए 120 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल उप-मण्डल में 5 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई हैं। लाहौल-स्पिति जिला परिषद के 10 वार्ड सदस्यों के लिए 41 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें काजा उपमण्डल में 10 तथा लाहौल उपमण्डल में 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

उन्होंने कहा कि चम्बा जिला की पांगी पंचायत समिति में 15 सदस्यों के लिए 52 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 16 पंचायतों में प्रधान पद के लिए 67 उम्मीदवार तथा उप-प्रधान के लिए 74 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और 80 वार्ड सदस्य पदों के लिए 148 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि शहरी निकायों के 23 सदस्यों के उप-चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसमें ऊना जिला की दौलतपुर नगर पंचायत के 7 वार्डों के लिए 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कांगड़ा जिला के कांगड़ा नगर परिषद में एक वार्ड सदस्य के पद के लिए 3 उम्मीदवार, नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला में दो वार्डों के लिए 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि मण्डी जिला की नेरचौक नगर पंचायत के 11 वार्डों में से एक वार्ड में जनवरी, 2016 में चुनाव सम्पन्न हो चुका है तथा शेष बचे 10 वार्डों के लिए 6 वार्डों में उम्मीदवारों ने अपने नाम वापिस लिए हैं तथा 4 वार्डों के लिए 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

उन्होंने बताया कि मण्डी जिला की करसोग नगर परिषद के लिए बचे 3 वार्डों में से एक वार्ड के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा है। शेष बचे दो वार्डों के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदान 17 व 19 जून, 2016 को प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक होगा और शहरी निकायों के लिए मतदान 17 जून, 2016 प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक करवाया जाएगा।

सामान्य भविष्य निधि विवरणियां सरकार की वैबसाईट पर उपलब्ध

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की वर्ष 2015-16 की सामान्य भविष्य निधि की वार्षिक विवरणियां सरकार की वैबसाईट www.himkos.nic.in पर उपलब्ध करवाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों की वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणियां को www.himkos.nic.in से डाउनलोड़ कर सकते हैं।

उन्होंने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिगत अपना पासवर्ड बदल लें तथा उसे सुरक्षित रखें। उन्होंने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र में आने वाले सभी कर्मचारियों की वर्ष 2015-16 की जीपीएफ स्टेटमेंट के अथशेष को अपने वेतन बिल रजिस्टर में अवश्य दर्ज करने के उपरान्त सभी कर्मचारियों को शीघ्र प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा इसकी अनुपालना से महालेखाकार हिमाचल प्रदेश शिमला को भी अवगत करवाएं। उन्होंने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है कि अपनी वार्षिक जीपीएफ स्टेटमेंट में दर्शाए गए आंकड़ों से स्वयं जांच करें और यदि उसमें कोई त्रूटि लगे तो जीपीएफ स्टेटमेंट प्राप्ति के तीन माह के भीतर महालेखाकार कार्यालय की वैबसाईट में कम्पलेंट बॉक्स पर दर्ज करें या agaehimachalprades/cag.gov.in पर ई-मेल अथवा पत्राचार द्वारा इस कार्यालय को सूचित करें।

मुख्यमंत्री से मिला घणागूघाट पंचायत का प्रतिनिधि मण्डल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से नई दिल्ली में सोलन जिला की पंचायत घणागूघाट के प्रधान धनीराम रघुवंशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल मिला तथा स्थानीय समस्याओं के बारे उन्हें अवगत करवाया।

धनीराम रघुवंशी ने मुख्यमंत्री से विशेषकर अनुरोध किया इस क्षेत्र में वर्ष 1962 से चल रही राजकीय प्राथमिक पाठशाला शेरपुर को मिडल स्कूल में स्तरोन्नत करने का अनुरोध किया ताकि बच्चों को स्कूल जाने के लिए कम दूरी तय करनी पड़े। उन्होंने प्राइमरी स्वास्थ्य उप केन्द्र घणागूघाट को अपग्रेड करके प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र करवाने का भी अनुरोध किया।

धनीराम रघुवंशी ने मुख्यमंत्री के ध्यान में यह बात भी लाई कि राजकीय मिडल स्कूल माण्डी को सीनियर सैकेन्डरी स्कूल सूरजपुर परिसर के तहत रखा गया है जबकि यह पाठशाला सीनियर सैकेन्डरी स्कूल घणागूघाट परिसर के तहत आनी चाहिए। उन्होंने इस सम्बंध में तुरन्त हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। धनीराम रघुवंशी ने पूर्व सांसद एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी रानी प्रतिभा सिंह का भी आभार व्यक्त किया कि उन्होंने हाल ही में घणागूघाट क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम अन्द्रोली व चमाहरी में हैण्ड पम्प स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने रानी साहिबा का इस बात के लिए भी आभार व्यक्त किया कि उन्होंने गांव काऊग के समीप शमशानघाट वर्षाशालिका के लिए 1,50,000/- रूपए स्वीकृत करवाये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन किया कि उनकी स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेंगे।

प्रेम की शक्ति दण्ड की शक्ति से हजार गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है।.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

रिटैन्शन पॉलिसी कब तक और क्यों

अवैध भवन निर्माणों को नियमित करने के लिये सरकार फिर रिटैन्शन पॉलिसी लेकर आयी है। इसके लिये अध्यादेश जारी किया गया है प्रदेश पहली बार 1997 में रिटैन्शन पॉलिसी लायी गयी थी तब वीरभद्र की सरकार ही थी। इसके बाद 1999, 2000, 2002, 2004, 2006 और 2009 में रिटैन्शन के नाम पर भवन निर्माण नियमों में संशोधन किये गये हैं। 2006 में जून और नवम्बर में दो बार यह पॉलिसी लायी गयी। रिटैन्शन के नाम पर अब तक प्रदेश में 8198 अवैध भवनों को नियमित किया जा चुका है। इस अवधि में प्रदेश में वीरभद्र और प्रेम कुमार धूमल दोनो की ही सरकारें रही है और दोनो के शासन कालों में बडे पैमाने पर अवैध भवन निमार्ण हुए है। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निमार्ण के लिये किसी तरह के कोई नियम नही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ही यह नियम लागू है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम ,नगर पालिका, एन ए सी आदि स्थानीय स्वशासन निकायों को भवन निर्माणो को रैगुलेट करने के अधिकार प्राप्त है। इन नियमों में यदि कोई भवन निर्माता छोटी – मोटी भूल कर जाता है। तो उसे नियमित करने का अधिकार भी इन निकायों को प्राप्त है। नियमित करने के लिये भी नियम पूरी तरह परिभाषित है। सामान्यतः अवैध भवन निर्माणों को लेकर सरकार के दखल की गुंजाईश बहुत कम रहती है। सरकार का दखल की आवश्यकता तब पडती है जब बडे पैमाने पर अवैध निर्माण सामने आते है जिनमें नियमों में ही संशोधन करना पड़ जाये।

प्रदेश में नौवी बार यह संशोधन होने जा रहा है। 1997 में जब पहली बार यह रिटैन्शन पॉलिसी लायी गयी थी तब यह दावा किया गया था कि इसके बाद होने वाले अवैध निर्माणों के साथ सख्ती से निपटा जायेगा। लेकिन बाद में हुआ सब कुछ इस दावे के ठीक उल्ट। सख्ती के नाम पर दलाली की फीस अवश्य बढ़ गयी है और यह दलाली बहुत लोगों का रोजगार बन गयी है। 1997 में रिटैन्शन जब पहली बार रिटैन्शन पॉलिसी लायी गयी थी तो उसके बाद फिर अवैध निर्माण कैसे हो गये? इस अवैधता के लिये उस सरकारी तन्त्र के खिलाफ क्या कारवाई की गयी जिसे यह सुनिश्चित करना था। कि उसके क्षेत्र में भवन निर्माण नियमों की अनुपालना ठीक से हो रही या नही। लेकिन जिस तरह से बार–बार रिटैन्शन के नाम पर भवन निर्माण नियमों में संशोधन हुए है। उससे यह संदेश जाता है कि सारी अवैधता एक सुनियोजित तरीके से होती आ रही है। इसक पीछे ऐसे लोग रहे है जा पूरी तरह आश्वस्त रहे है जो यह जानते थे कि निर्माण के दौरान सरकारी तन्त्र उनका काम रोकने नही आयेगा और बाद मे वह इसे रिटैन्शन के नाम पर नियमित करवा लेगें।

आज अगर शिमला में ही नजर दौड़ायी जाये तो सबसे ज्यादा अवैध निर्माण यहां पर हुए है। यहा पर नगर निगम के जिम्मे भवन निर्माणों पर निगरानी रखने का काम था। लेकिन यहां पर होटल बिलो बैंक में जिस तरह से अवैध निर्माण ठीक मालरोड़ पर होता रहा और जैसे उसे नियमित किया गया है उसमें सरकार से लेकर नगर निगम तक पूरा संवद्ध तन्त्र की सवालों के घेरे में आ जाता है। सही पर प्रदेश उच्च न्यायालय का अपना भवन अवैध निर्माणों की सूची में शामिल है जब नगर निगम शिमला के क्षेत्र में अवैध निर्माणों को लेकर विधान सभा में स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज का प्रश्न आया था तो उसके उत्तर मे जो सूची में शामिल रखी गयी थी उसे कई सरकारी भवन भी शामिल रहे है। जबकि नियमो के मुताबिक सरकारी भवनों को भवन निर्माण नियमों की अनुपालना न करने की छूट नहीं हैं। आज कोर्ट रोड़ पर जिस तरह के विधायक बलवीर शर्मा का होटल बना है उस पर अवैधता का सबसे बड़ा आरोप है। आज हर व्यक्ति यह कहता सूना जा सकता है कि इस बार रिटैन्शन पोलिसी इन लोगो के लिए लाई जा रही है। बार– बार भवन निर्माण नियमों में संशोधन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में बिल्डर लॉबी कितनी प्रभावशाली हो चुकी है नगर निगम शिमला और प्रदेश विधान सभा चुनावों से पूर्व हर बार बिल्डर लॉबी को खुश करने के लिए भू अधिनियम की धारा 118 और भवन निर्माण नियमों में सरकारें संशोधन लाती रही है। हर बार लायी गई रिटैन्शन को आखिरी बार कहा जाता रहा है लेकिन हुआ ठीक उससे उल्टा है। इसलिए बार – बार नियमों में संशोधन लाने की बजाये इन नियमों को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये और एक तय सीमा के बाद हर अवैधता की एक फीस का प्रावधान कर दिया जाना चाहिये।

फसल विविधिकरण से आया किसानों की आर्थिकी में बदलाव

प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और राज्य की आर्थिकी में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है, जहां 89.96 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में बसती है और 70 प्रतिशत लोग सीधेतौर पर कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सम्बद्ध गतिविधियों का 10.4 प्रतिशत योगदान है। राज्य में 5.42 लाख हैक्टेयर भूमि काश्त की जाती है और 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की कृषि जलवायु नकदी फसलों जैसे आलू, बेमौसमी सब्जियों और अदरक उत्पादन के लिये अति उत्तम है।

- **321 करोड़ की फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना कार्यान्वित**
- **राज्य में 870जलस्त्रोत तथा 4700 पॉलीहाऊस स्थापित किए जा रहे हैं**
- **राज्य में 16.74 लाख मीट्रिक टन खाद्यानों का उत्पादन**

प्रदेश सरकार कृषि तथा इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। वर्ष 2016 – 17 के लिए सरकार ने कृषि विकास के लिए 482 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है।

प्रदेश में कृषि विविधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में जून, 2011 से 321 करोड़ रुपये की 'हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना' जापान इन्टरनेशनल को आपरेशन एजेंसी के सहयोग से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत कृषि विविधिकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ किया जा सके। इसके

अन्तर्गत किसानों को सिंचाई सुविधाएं, खेतों तक सड़क मार्ग, जैविक खेती तथा किसानों के समूह गठित कर सब्जी उत्पादन व विपणन के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाना शामिल है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के पाँच जिलों- बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा व ऊना में सात वर्षों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत 210 लघु सिंचाई योजनाऐं, 147 सम्पर्क मार्ग, 37 एकत्रण केन्द्र स्थापित करके सब्जी उत्पादन को विशेष महत्व दिया जाएगा। योजना के तहत वर्ष 2015. 16 के दौरान 60 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि वर्ष 2016 – 2017 के लिये 80 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

सरकार द्वारा फसल विविधिकरण तथा बेमौसमी सब्जियों को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र में आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने के लिए 111.19 करोड़ रूपये की 'डा. वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना' कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पॉलिहाऊस तथा सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, किसानों को पॉलिहाऊस, ड्रिप इकाईयां व स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिए 85 प्रतिशत का उपदान प्रदान किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 – 15 से 2017 – 18 तक 4700 पॉलीहाऊस व 2150 स्प्रिंकलर/ड्रिप इकाईयां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा, 870 पानी के स्त्रोत जैसे लघु लिफ्ट, मध्यम लिफ्ट और पम्पिंग मशीनरी इत्यादि स्थापित किये जाएंगे और इसके लिये 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत 8.35 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को संरक्षित खेती के तहत तथा 8.20 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। गत वित्त वर्ष में योजना पर 25 करोड़ रूपये खर्च किये गये, जबकि वर्ष 2016 – 2017 में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के अंर्तगत अब तक 1276 पॉलीहाउस का निर्माण करवाकर 2. 34 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को संरक्षित खेती के अंर्तगत लाया गया है।

कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में चार प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना तथा किसानों की आय बढ़ाना है।

प्रदेश में धान, मक्की, दालों और गेहूँ का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान' आरम्भ किया गया है, जिसके तहत उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत 17.88 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, जबकि धान की फसल को बढ़ावा देने के लिए 1.36 करोड़ रुपये, गेहूँ के लिए नौ करोड़ रूपये, मक्की के लिए 3.19 करोड़ रूपये व दालों के लिए 4.33 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश मे वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान 9.4 लाख टन खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 7.50 लाख टन मक्की, 1.31 लाख टन धान की उपज का लक्ष्य शामिल है। तिलहन के लिए 4.8 हजार मीट्रिक टन तथा आलू का 1.95 लाख मीट्रिक टन, अदरक 35 हजार टन तथा सब्जी 15 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं, जिसके तहत किसानों को 25.60 क्विंटल उन्नत बीज, 22 हजार टन रासायनिक खाद, 100 क्विंटल जीवाणु खाद व 95 टन दवाईयों के अतिरिक्त, 55 हजार सुधरे औजार किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार के प्रयासों से वर्ष 2014 – 15 में राज्य में 16.74 लाख मीट्रिक टन खाद्यान का उत्पादन हुआ, जबकि इसी दौरान 1.81 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ।

सरकार के दो वर्ष

नए दौर में संस्कृति और परंपराओं को बचाने की सार्थक पहल

– अतुल सिन्हा –

बदलते दौर में संस्कृति और परंपराओं के साथ-साथ अपने देश के गौरवशाली इतिहास को बचाने की चुनौती हर सरकार के सामने रही है। केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में लगातार कोशिशें करता रहा है। तमाम कार्यक्रमों और योजनाओं के ज़रिए संस्कृति के विकास और संरक्षण के काम होते रहे हैं। लेकिन पिछले दो साल इस मामले में सबसे अहम रहे हैं। दरअसल इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक बनाने, इतिहास और परंपराओं में रूचि पैदा करने की दिशा में तेजी से काम हो रहे हैं। 'डिजिटल इंडिया' महज नारा नहीं रह गया है बल्कि इसे ज़मीनी हकीकत बनाने में मंत्रालय के तमाम विभागों ने काफी सक्रियता दिखाई है। अगर आप संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं तो यह एहसास आपको खुद हो जाएगा कि इसमें कितना बदलाव आया है और कितनी तेजी से आपको संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में नए अपडेट्स मिल रहे हैं। मंत्रालय का मोबाइल ऐप 'संस्कृति' इस दिशा में एक अहम कदम है।

सरकार के लिए अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाना, इससे नई पीढ़ी को जोड़ना और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को भरपूर मदद देना सरकार की प्राथमिकताओं में है। निजी तौर पर संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा की दिलचस्पी अपने देश की कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, रंगमंच के अलावा अपनी परंपराओं और धरोहरों के संरक्षण में है और उनकी सक्रियता इस दिशा में लगातार दिखाई देती रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र महज सफेद हाथी बन कर न रह जाए, इसके लिए इसके स्वरूप में आमूल चूल बदलाव लाने की पहल हो चुकी है। संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अब पहले से कही ज्यादा सक्रिय हैं।

आम तौर पर सांस्कृतिक महोत्सवों और कला मेलों में आने वाले कलाकार अपनी उपेक्षा और आयोजकों के रवैये से नाराज़ रहते हैं, ऐसे आयोजनों को दिखावा और महज कुछ लोगों के फायदे के लिए बताते हैं लेकिन जिस तरह दिल्ली में आठ दिनों तक चला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इस बार संपन्न हुआ और तकरीबन दो हज़ार से ज्यादा कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया वह अपने आप में अनूठा था। यहां संगीत का हर रंग दिखा, लोक कला के तमाम आयाम नज़र आए, सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने हर विधा से जुड़े कलाकारों को मंच और सुविधाएं प्रदान की, सरकार के तमाम मंत्रीगण समेत कला-संस्कृति से जुड़ी जानी मानी हस्तियों ने इसमें गहरी रूचि दिखाई, यह एक बड़ी उपलब्धि है।

दूसरी तरफ आर्ट ऑफ लिविंग के विश्व संस्कृति उत्सव में जिस तरह हज़ारों कलाकारों ने दिल्ली के यमुना तट पर बने विशालकाय और बेहद आकर्षक मंच पर तीन दिनों तक समां बांधा और प्रधानमंत्री, सहित अनेक मंत्रियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, वह अपने आप में एक यादगार और अनूठी पहल है। यही से गंगा के साथ साथ यमुना की सफाई को लेकर भी एक नई जागरूकता दिखाई पड़ी।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस पिछले कई दशकों से सियासत के केन्द्र में रहे हैं। उनके बारे में हर उपलब्ध दस्तावेज़ सार्वजनिक करने का काम करके सरकार ने आम लोगों के भीतर बनी नेताजी की अबूझ पहेलियों को सुलझाया, उनकी विरासत को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ाने की पहल की और उनके 119वें जन्मदिवस पर लोगों को ये तोहफा दिया कि वे अब ये सारे दस्तावेज़ कभी भी इंटरनेट पर देख सकते हैं। साथ ही नेताजी के परिवारवालों को नई पहचान दिलाई गई। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय अभिलेखागार) की 125वीं सालगिरह पर हुए कार्यक्रम में नेताजी के भाई अमियनाथ बोस से जुड़े दस्तावेज भी अभिलेखागार को सौंपे गए।

अपने देश के पुरातत्व और इतिहास से जुड़े दस्तावेजों को लेकर, अपने धरोहरों को बचाने और इनके पुनरुद्धार को लेकर कई कोशिशें हो रही हैं। खासकर इन संस्थाओं और विभागों के डिजिटाइजेशन के साथ साथ इनसे जुड़ी सूचनाओं को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने और इन्हें सहेजने के काम ने तेजी पकड़ी है। कई ऐसे वेब पोर्टल और ऐप विकसित किए गए हैं जिनके ज़रिए अब हर जानकारी आम आदमी की पहुंच में आ गई है। सबसे अहम काम हो रहा है उन उपेक्षित स्मारकों की सफाई का जहां बिखरी गंदगी और अव्यवस्था से कोई वहां जाना पसंद नही करता। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 'स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्मारक' का नारा अब ज़मीन पर उतारने की कोशिश जारी है।

गंगोत्री से गंगासागर तक करीब 262 क्षेत्रों से होकर गुज़री गंगा संस्कृति यात्रा ने करीब ढाई करोड़ लोगों के बीच गंगा के प्रति आस्था और इसकी सफाई को लेकर जागरूकता पैदा करने का काम किया। गंगा को सांस्कृतिक एकता और आस्था का प्रतीक और तमाम नदियों के विकास और संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे कदम भी सरकार की उपलब्धियों में गिने जा सकते हैं। खासकर वाराणसी के विकास और गंगा के साथ साथ वरुणा और अस्सी जैसी नदियों के अस्तित्व को बचाने को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री और संस्कृति मंत्री ने निरंतर कोशिशें की हैं, उसकी वाराणसी में ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा है। संस्कृति के विस्तार, इसके संरक्षण और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने की कोशिशों के साथ साथ एक सबसे बड़ा काम उन कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों के डाटाबैंक बनाने का भी है, जिससे देशभर के उन तमाम लोगों की पहचान की जा सके जो वास्तव में कला और संस्कृति के लिए समर्पित हैं या जिनका कोई न कोई योगदान इस क्षेत्र में है। इससे उन कलाकारों को पहचानने और उनकी जीवन शैली के साथ साथ कला और परंपरा को बेहतर बनाने की दिशा में काफी फायदा होने वाला है। अब तक तकरीबन 55 लाख संस्कृतिकर्मियों और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों व संस्थाओं का डाटा बैंक तैयार हो चुका है।

आमतौर पर सरकारी योजनाओं और इन्हें ज़मीनी स्तर पर उतारने को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसे पारदर्शी बनाने और वास्तव में लोक और आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ कलाकारों के हित में काम करने की ये पहल उम्मीद जगाने वाली है। इसका अंदाज़ा मौजूदा बजट में संस्कृति मंत्रालय के लिए 17.5 फीसदी की गई बढ़ोत्तरी से लगाया जा सकता है। इस बार संस्कृति मंत्रालय को अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 2500 करोड़ रूपए का बजट दिया गया है। जाहिर है अगर इस बजट का सही और व्यावहारिक इस्तेमाल होता है तो कोई संदेह नहीं कि अपने देश की कला, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं और धरोहर सुरक्षित ही नही रहेगी, लगातार फले फूलेगी और नई पीढ़ी इसके रंग को बेहतर तरीके से समझ पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि सही व्यक्तियों और संस्थाओं की तलाश की जाए, उनके कामकाज, अनुभव और ईमानदारी की जांच हो और फिर समर्पित तरीके से काम करने वालों की ऐसी टीम पूरे देश में सक्रिय रहे जो न सिर्फ संस्कृति को समझती हो, बल्कि इसे आज के संदर्भों में जोड़कर, इसे सामयिक बनाकर और हाशिए पर पड़े कलाकारों को मुख्य धारा में लाकर काम करे। आज सचमुच ज़रूरत है उन कलाओं को बचाने की जो विलुप्त हो रही हैं। उन कला रूपों को, भाषा और बोलियों को, संगीत और नृत्य शैलियों को बचाने और उनके लिए ऐसे नए संस्थान, प्रतिष्ठान और अकादमियां बनाने की आज ज़रूरत है जो ज़मीनी स्तर पर काम कर सकें।

पसूका

परम्पराओं में परिवर्तनः एक सामयिक आवश्यकता

शिमला। भारतवर्ष पारम्परिक संस्कृतियों का देश है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान रखने के बावजूद भी हम भारतवर्षी बहुत ज्यादा परम्परावादी हैं या यों कहें कि हमारा प्रत्येक क्रियाकलाप थोड़ा बहुत परंपरागत अवश्य होता है। वो बात अलग है कि हमारी प्रत्येक परम्परा में कोई न कोई वैज्ञानिकता अथवा औचित्य अवश्य छिपा होता है, चाहे वह हमे ज्ञात हो ना हो। परम्पराओं का निर्वाहन हमें किसी भी कीमत पर करना ही होता है। अब सवाल यह है कि आज के इस तीव्र परिवर्तनशील सांस्कृतिक परिवेश में परम्पराओं में परिवर्तन भी क्या एक सामयिक आवश्यकता बनती जा रही है? हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा पशुबलि प्रथा पर रोक, देश में विभिन्न समुदायों में मृत्युभोज पर रोक, राजस्थान में सतीप्रथा पर रोक आदि कदम परम्पराओं में सामायिक परिवर्तन को इंगित करते हैं। अब अध्ययन का विषय यह है कि इस तरह के परिवर्तन हमारे लिए लाभदाई हैं या फिर हानिकारक।

प्राचीन परम्पराएँ किसी औचित्य को लेकर शनेः शनेः प्रारम्भ हुई। कालान्तर में इनमे कुछ अच्छाईयां तो कुछ बुराइयाँ जुड़ती चली गई। बहुत सारी परम्पराओं ने कुछ और ही रूप धारण कर लिया। धार्मिक यज्ञों में मनुष्य की पाशविक प्रवृति अथवा पशुत्व की बलि का स्थान पशुबलि ने ले लिया, तो तामसिक प्रवृति और स्वाद लोलुपों को इस तरह की परम्पराएँ औचित्य से भरपूर प्रतीत हुई। पशुओं को आपस में लड़ाने की परम्परा भी शक्ति प्रदर्शन एवं मनोरंजन जैसे औचित्य लिये थी, जिसने बाद में वीभत्स रूप लिया और प्राणिमात्र पर अकारण अत्याचार का कारण बनी। सतीप्रथा का प्रारम्भ पति-परमेश्वर के प्रति अगाध प्रेम एवं समर्पण से प्रारम्भ हुआ जिसने कालान्तर में हत्या का रूप ले लिया।

गीतोपदेश के अनुसार परिवर्तन संसार का नियम है। जहाँ परिवर्तन नहीं, वहां परिवर्धन नहीं और जहाँ परिवर्धन नहीं वहां सृष्टि-निर्माण का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। फिर सांस्कृतिक परम्पराओं में परिवर्तन क्यों नहीं? क्या आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता को हम परम्पराओं से बलात जोड़कर उसके साथ छल तो नहीं कर रहे? क्या हमारी यह सोच उचित है कि प्राचीन परम्पराएँ बिना किसी परिवर्तन, परिवर्धन के हमें सांस्कृतिक उत्थान की ओर ले जाएंगी?जी नहीं। प्राचीन एवं अनर्थक हुई परम्पराओं में नवीनता का संचार करना भी तो परम्परा होनी चाहिए। हमारी संस्कृति एवं परम्पराएँ किसी रुके हुए गदे नाले की तरह नहीं, बल्कि एक बहती नदी की तरह होनी चाहिए, जो सदैव स्वच्छ एवं निर्मल रह सके। संस्कृति एवं परम्पराओं के द्वार चहुंमुखी एवं सदैव खुले होने चाहिए ताकि इनमे निरंतर नवीनता का संचार होता रहे।

हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मेलों में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही झोटों की लड़ाई भी अपने आप में एक अनूठी परम्परा थी, मगर समय के साथ इसकी सार्थकता एवं औचित्य कम होने लगी एवं अंततः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमे परिवर्तन करना पड़ा। आज हमारे पास मनोरंजन के असंख्य साधन मौजूद हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी और बहुत से उपाय खोज लिए गए है, फिर पशुओं के साथ यह क्रूरता क्यों। प्राणीमात्र के सम्मान के रूप में हमारा यह कदम स्वागत योग्य है। भावी पीढ़ियां जब अपने इतिहास का अध्ययन करेंगी तो उन्हें ज्ञात होगा कि अपने पूर्वजों द्वारा संस्कृति के द्वार खुले रखने के कारण ही हम एक सुसंस्कृत एवं सुसंस्कारित देश में जन्म ले सके। परम्पराओं में परिवर्तन आज एक सामयिक आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृतियों के द्वार खुले रखकर उनमें नित्य नवीनता का अनुभव पा सकते हैं।

– डा. महेश कुमार वर्मा –
प्रबंधक, NMDC लिमिटेड, शिमला

सदियों पुरानी विधा 'जादू' को जीवित रखने की आवश्यकता: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में परिजनों सहित सुप्रसिद्ध जादूगर सम्राट शंकर का शो देखा और इस शो में गहरी रूचि ली।

राज्यपाल ने सम्राट शंकर को हिमाचली शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया तथा द्वीप प्रज्जवलित कर शो का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर आचार्य देवव्रत ने कहा कि 'जादू' भारत वर्ष की सदियों पुरानी विधा है, जो अब लगभग लुप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बेशक जादू का प्रदर्शन पूर्णत: वैज्ञानिक एवं हाथ की सफाई है, लेकिन यह एक ऐसी विलक्षण विधा है, जो सभी को विस्मित कर देती है।

राज्यपाल ने कहा कि हमें गौरव है कि सम्राट शंकर ने इस विद्या को न केवल जीवित रखा है, बल्कि इसे आगे भी बढ़ा रहे हैं, और इन्होंने देश व विदेश में अपने जादू की अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि सम्राट शंकर का समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जादू न केवल दर्शकों का स्वस्थ मनोरंजन करता है, बल्कि कन्या की महत्ता, जल ही जीवन है, पर्यावरण संरक्षण, भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोकने का एक प्रभावी सन्देश भी देता है।

इससे पूर्व, सम्राट शंकर ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें हिमाचल के लोगों से विशेष लगाव है, और लोग उनके प्रदर्शन को बेहद पसन्द करते हैं, जिस कारण वे बार-बार यहां आना पसन्द करते हैं। सम्राट शंकर ने कहा कि उन्होंने देश व विदेशों में आज तक लगभग 27 हजार शो किए हैं, जिनमें से करीब 20 हजार शो चैरिटी के लिए किए हैं।

शिक्षा विभाग में तबादलों एवं तैनातियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा विभाग में तबादलों एवं तैनातियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के ध्यान में आया है कि शिक्षा विभाग में अभी भी कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं, जो निर्देशों का उलंघन है और सरकार ने इसे गम्भीरतापूर्वक लिया है।

उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए केवल अपरिहार्य परिस्थितियों एवं प्रशासनिक कारणों से जुड़े स्थानान्तरण एवं तैनाती प्रस्तावों की प्रक्रिया प्रशासनिक विभाग तथा मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति से क्रियान्वित की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि इन निर्देशों की अनुपालना की जानी चाहिए तथा उलंघन की स्थिति में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई अमल में लाई जाएगी।

शिमला एयरपोर्ट के पुनरुद्धार के निर्णय पर सी.आई.आई. ने की सरकार की प्रशंसा

शिमला/शैल। भारतीय उद्योग परिसंघ ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 4 वर्ष से उड़ानों से दूर रहे शिमला एयरपोर्ट के पुनरुद्धार करने के निर्णय का स्वागत किया है।

सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन संजय खुराना ने कहा कि शिमला उत्तरी क्षेत्र के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक है और देश भर से सारा वर्ष यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती एयरकनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि वे तहे दिल से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला एयरपोर्ट के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं और इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। यह पहाड़ों वाले इस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बेहद अहम निर्णय है। एयरपोर्ट न केवल पर्यटकों को बल्कि उद्योग क्षेत्र को भी बढावा देने में अहम साबित होगा। सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश साहू ने कहा कि सी.आई.आई. को उम्मीद है कि राज्य जल्द ही देश के बड़े और प्रमुख शहरों से एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ जाएगा। ऐसा होना प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने किया 'किन्नौरी लोकमानस व डायन कथा रहस्य' का विमोचन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शरभ नेगी की पुस्तक 'किन्नौरी लोकमानस और डायन कथा रहस्य' का लोकार्पण किया। उन्होंने लेखक को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की सांस्कृतिक धरोहर को लेकर अधिकाधिक शोध और लेखन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों का लोक साहित्य बहुत समृद्ध है, इसके माध्यम से ही यहां के इतिहास ओर अतीत के संघर्षपूर्ण जीवन और समाज का बोध हो सकता है।

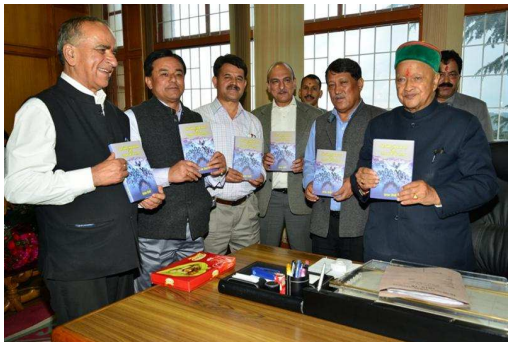

उल्लेखनीय है कि शरभ नेगी की यह तीसरी पुस्तक है, जिसमें किन्नौर की डायन सम्बंधी लोक कथाओं को आधार बनाकर किन्नौरी लोकमानस का अध्ययन किया गया है। इस पुस्तक के प्राक्कथन में डा. तुलसी रमण का मानना है कि लोक कथाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण की यह पहल लोक साहित्य के नए पुनर्पाठ का उदाहरण है। इस विधा के अध्येताओं के लिए यह पुस्तक एक नई दिशा देने वाली साबित होगी। इस अवसर पर अनेक अधिकारी एवं साहित्यकार उपस्थित थे। शरभ नेगी की इससे पूर्व दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 'हिमालय पुत्र किन्नरों की लोकगाथाएं' एवं 'डोडरा क्वार' हैं। क्षेत्रीय संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित उनकी पुस्तक 'डोडरा क्वार' विशेष चर्चित और प्रशंसित हुई है।

शरभ नेगी गत वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त हुए हैं। उन्होंने चम्बा तथा कुल्लू के जिलाधीश के पदों पर रहने के अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। नेगी किन्नौर जिला के जंगी गांव के मूलनिवासी हैं, इन दिनों सोलन में भी रह रहे हैं। लोक संस्कृति विषयक के लेखन की कुछ अन्य योजनाओं पर भी नेगी काम कर रहे हैं।

पंजाब के सैलानियों की मौत पर वन मंत्री द्वारा शोक व्यक्त

शिमला/शैल। वन मन्त्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने नारकण्डा स्थित प्रदेश वन विकास निगम के इको-टूरिजम स्थल पर गत देर रात आए भारी तूफान के कारण टैन्ट पर पेड़ गिरने से मारे गए पंजाब के दो सैलानियों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रदेश वन विकास निगम पठानिया ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। घटना की सूचना मिलते ही वन मन्त्री ने वन विकास निगम के अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने व प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये।

गौरतलब है कि नारकण्डा स्थित हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के इको-टूरिजम स्थल पर गत 8 जून की रात को लगभग 3 बजे भारी आंधी और तूफान के कारण कायल का एक बड़ा वृक्ष टूट कर दो टैन्टों पर गिर गया, जिस कारण एक टैन्ट में ठहरे 3 सैलानियों में से राजेश कुमार 36 और अशोक सिद्धु 45 की मौत हो गई जबकि गगन आजाद को मामूली चोटें आई हैं। ये तीनों शिक्षा विभाग जालन्धर से यहां घुमने आऐ थे।

अर्थव्यवस्था की मजबूती में उद्योगों की भूमिका अहम: स्टोक्स

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा कि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका अहम् होती है। उद्योगों से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

स्टोक्स यहां पी.एच.डी. चौंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा हिमाचल पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित चौथे हिमालयन कंज्यूमर फेयर का उद्घाटन करने के उपरान्त हिमाचल व पड़ोसी राज्यों से आए हुए कारोबारियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां उद्योगों व उद्योगपतियों की सुविधा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि उद्योगपतियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जा सके। विद्या स्टोक्स ने पी.एच.डी. चौंबर ऑफ कामर्स के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हिमालयन फेयर में पड़ोसी राज्यों के कारोबारियों के भाग लेने से न केवल हिमाचल प्रदेश के कारोबार के क्षेत्र में पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्ते मजबूत होंगें, बल्कि सभी प्रदेशों के कारोबारियों को अपने उत्पाद एक दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का भी मौका मिलेगा।

इस अवसर पर पी.एच.डी. चौंबर के अध्यक्ष महेश गुप्ता ने कहा कि पी.एच.डी. चौंबर का हमेशा यह प्रयास रहता है कि कारोबारियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए, जहां वह अपने उत्पादों का बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें।

उन्होंने बताया कि इस समय पी.एच.डी. चौंबर के साथ डेढ हजार से अधिक कारोबारी सीधे तौर पर, तथा 45000 परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। पी.एच.डी. द्वारा अपनी शाखाओं का देश के विभिन्न राज्यों में लगातार विस्तार किया जा रहा है। पी.एच.डी. चौम्बर द्वारा हर साल पंजाब में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया जाता है। पी.एच.डी. चौंबर ऑफ कामर्स के क्षेत्रीय निदेशक डा. प्रवीन राठी ने बताया कि चौंबर द्वारा शिमला में इस तरह के तीन आयोजन किए जा चुके हैं। हिमाचल में भी अब इस आयोजन का विस्तार किया जा रहा है, जिसके चलते इसी माह धर्मशाला में भी इस तरह का एक और आयोजन किया जा रहा है।

पी.एच.डी. चौंबर शिमला चौप्टर के चेयरमैन ध्यान चंद तथा को-चेयरमैन आशीष बगरोडिया ने कहा कि शिमला में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों एवं उद्योगपतियों की मांग को देखते हुए इस बार हिमालयन कंज्यूमर फेयर का विस्तार किया गया है। 12 जून तक चलने वाले हिमालयन फेयर में इस बार हिमाचल के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हैदराबाद के कारोबारी अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे।

किसानों को दी जा रही राहतों और अनुदानों में लगातार कमी की जा रही:कुलदीप तंवर

शिमला/शैल। माकपा के राज्य सचिवालय सदस्य व पूर्व आईएफएस अफसर कुलदीप सिंह तंवर ने मोदी सरकार की मंत्री मेनका गांधी व सोनिया गांधी की करीबी कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी को सलाह दी कि वे आरामदायक वातानुकूलित कमरों से बाहर निकले और देश भर के गांवों में बसने वाले किसानों की समस्याओं को समझे। उन्होंने आगाह किया कि यदि इसी तरह किसान विरोधी रूख पक्ष व विपक्ष का रहा तो देश के किसानों में अलगाव एवं विरोध की भावना ही बढ़ेगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मेनका गांधी व वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से दिए जा रहे ब्यानों के मद्देनजर उनकी जुबान पर लगाम लगाने का आग्रह किया है।

पूर्व आईएफएस अफसर ने इसके अलावा जंगली जानवरों पर मोदी सरकार व प्रदेश की वीरभद्र सरकार को जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने व उनके प्रबन्धन के मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।

उन्होंने कहा कि किसान आन्दोलनों के दबाव के चलते मोदी सरकार ने हाल में कुछ राज्यों में बंदरों, जंगली सुअरों एवं नीलगायों को वन्यप्राणी संरक्षण कानून 1972 के तहत वर्मिन घोषित किया था। मोदी सरकार के मंत्री इस मामले में आपस में ही उलझ गए हैं जो कि खेदपूर्ण है। उन्होंने राज्यसभा की उपसमिति की अध्यक्षा रेणुका चौधरी के ब्यान को किसान विरोधी बताया जिसमें उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों को वर्मिन घोषित करने के निर्णय का विरोध किया था।

किसानों की जमीनी हालात से बेखबर शहरों में बैठ कर ब्यान देने वाले हवाई मंत्रियों के ब्यानों पर माकपा ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए है कि मंत्रियों के ऐसे ब्यानों पर तुरंत रोक लगाएं।

हिमाचल प्रदेश के किसान पिछले कई दशकों से जंगली जानवरों के सही प्रबन्धन की मांग कर रहे हैं ताकि किसानों की फसलें बच सकें। किसानों को दी जा रही राहतों और अनुदानों में लगातार कमी की जा रही है वहीं खाद्य, कीटनाशकों के बढ़ते दामों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसान को प्राकृतिक आपदा, सूखा और बाढ़ के बाद मण्डी में उचित मूल्य के लिए जूझना पड़ता है। उपर से जंगली जानवरों के उपद्रव ने किसानों की भूमि को बंजर रखने पर मजबूर कर दिया है। प्रदेश में सालाना 400 से 500 करोड़ रूपये की फसलें जंगली जानवरों के द्वारा नष्ट की जा रही हैं।

80,000 हैक्टयर के करीब भूमि को परती रखने की वजह से भी तकरीबन 400 और 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। फसलों की रखवाली करने के लिए लगे नौजवानों, बुजुर्गों एवं महिलाओं के दिहाड़ी से होने वाले 1200 करोड़ के नुकसान को भी जोड़ दिया जाए तो किसानों को सालाना 2000 से 2200 करोड़ का नुकसान हो रहा है।

हिमाचल में भूमि का सबसे ज्यादा हिस्सा (तकरीबन 67 फीसद) वन विभाग के अधिकार में हैं और उसमें भी 15 फीसद हिस्सा जंगली जानवरों, पशु-पक्षियों के लिए PAN के रूप में संरक्षित रखा गया है। प्रदेश में सिर्फ 17.14 फीसद भूमि ही किसानों के पास है और उसमें से भी 11.17 फीसद पर ही खेती हो सकती है। सरकारी एवं नीजि क्षेत्र में नौकरियां कम होने की वजह से लोग अपनी आजिविका के लिए मजदूरी एवं खेती पर भी निर्भर है। ऐसे में यदि वर्तमान एवं भूतपूर्व केन्द्रिय मंत्रियों के असंवेदशील ब्यान पक्ष एवं विपक्ष के किसान विरोधी रूख को उजागर करते हैं।

माकपा ने पशु प्रेमी संगठनों को भी चेताया कि वे किसान विरोधी फैसलों के पक्ष में न खडे हों। उन्होंने कहा कि वे लोग अच्छे हो सकते हैं परन्तु उनकी मंशा एवं काम किसान विरोधी है।

डॉ0 तंवर ने सपष्ट किया कि जंगलो की वहन क्षमता से ज्यादा हो गए जंगली जानवरों का वैज्ञानिक प्रबंधन जरूरी है और वैज्ञानिक कलिंग भी इसका हिस्सा है। उन्होने बताया कि अफिका में हाथी, आस्ट्रलिया में जंगली बिल्ली एवं कंगारू तथा इंग्लैड एवं कनाडा में सील के प्रबन्धन के लिए उन देशों की सरकारें अपनी देखरेख में वैज्ञानिक तौर पर कलिंग का सहारा लेती हैं। उन्होने कहा कि जंगली जानवरों का पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है परन्तु मानव की कीमत पर नहीं।

उन्होने कहा कि बंदरों का निर्यात जैव विज्ञान शोधों के लिए किया जाना चाहिए। ताकि एक तरफ किसानों को राहत मिल सके दूसरी तरफ मानव जाति के हितों में होने वाले जैव विज्ञानी शोधों में भी मदद मिल सके। उन्होने कहा कि बंदरों के शोध के लिए उपलब्ध न हो पाने की वजह से विकासशील देशों में दवाई बनाने वाली कम्पनियां सीधे मानवों पर ही शोध कर रही है जो कि अमानवीय है।

सभी जातियों व हर वर्ग के नवयुवको, नवयुवतियों, विदूर, विधवा व तलाकशुदा को योग्य जीवनसाथी मिलाने में निरन्तर सफलता हासिल कर रही प्रदेश की एकमात्र विश्वसनीय समाजसेवी संस्था द्वारा संचालित।

"आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो" पालमपुर केवल दस वर्षों में 8000 से अधिक जोडियां मिलाने का श्रेय प्राप्त कर चुकी है। हमारे पास हर प्रकार के रिश्ते उपलब्ध है। तथा उपलब्ध करवाये जाते है। जरूरतमन्द सम्पर्क करे :-

आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो

इन्द्रपुरी मार्किट नजदीक नया बस अड्डा पालमपुर

दूरभाष : 01894–230260 मोबाईल : 98163–22434

VAR-CHAHIYE

Suitable Match for Rajput Girl, 1990, 5'-5", B.A. Working H.P. Police, 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Rajput Girl, 1989, 5'-2", B.Tech (C.S.), Working at Gurgaon. Rs. 25,000/- Pm., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Rajput Girl, 1992, 5'-2", B.Sc. (Nursing), 01894-230260, 98163-22434

Suitable Match for Rajput Girl, 1989, 5'-3", MBA (Mkt.), Working at Delhi. Rs.30,000/- Pm., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Rajput Girl, 1992, 5'-1", B.Tech Working at Hydrabad. Rs. 4 Lacs /- PA., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Rajput Girl, 1988, 5'-5", B.Com. Diploma in HRD., Working at Gurgaon. Rs. 4.2 Lacs PA., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match forBrahmin Girl, 1990, 5'-2", Diploma G.N.M. & Diploma DCA., 01894-230260, 98163-22434.

VADHU-CHAHIYE

Suitable Match for Brahmin Boy, 1983, 5'-6", BA. Diploma H.M & 3 Year's Diploma Auto Mobile., Working at Una., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Brahmin Boy, 1986, 5'-3", BA., Electronics I.T.T.., Working at Ludhiana., Rs. 15,000/- Pm., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Brahmin Boy, 1986, 5'-7", B.Tech. (CSE) MBA., Working at Banglore., Rs. 5 Lacs PA., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Choudhary Boy, 1985, 5'-51/2", B. Com.,3 year's Course Architech, Working at Delhi, Rs.40,000/-Pm., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Mehra Boy, 1983, 5'-8", BA. Working at Abudabi Rs. 80,000/- Pm., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Brahmin Boy, 1988, 5'-9", BA. Working own Business , Rs. 15 to 17 Lacs PA., 01894-230260, 98163-22434.

Suitable Match for Brahmin Boy, 1985, 5'-11", CCNA. Doing MCA. Working as I.T. Coy. At Noida. Rs. 25,000/- Pm., 01894-230260, 98163-22434.

साहित्य, संगीत व कला के लिए अकादमी पुरस्कारों से नवाजी हस्तियां

शिमला/शैल। हिमाचल हिन्दी साहित्य के लिए सुरेश सेन निशांत, मुरारी शर्मा तथा डॉ. ओम प्रकाश शर्मा को हिमाचल साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जबकि अंग्रेजी साहित्य का पुरस्कार निधि चावला ने हासिल किया और पहाड़ी साहित्य के लिए डॉ. प्रिया शर्मा को पुरस्कृत किया गया। ये पुस्कार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा लेखकों, कलाकारों तथा पहाड़ी चित्रकला और चम्बा रूमाल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रदान किए।

कला श्रेणी में मुख्यमंत्री ने प्रो. एन.सी. सक्सेना, ओम प्रकाश सुजानपुरी, प्रेम प्रकाश निहाल्टा तथा बसंती देवी को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान और नाटय रंगमंडल मंडी स्वयं सेवी संस्था को राज्य में कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन की दिशा में किये गये प्रयासों के लिए सम्मानित किया।

पहाड़ी चित्रकला प्रतियोगिता की श्रेणी में अंशु मोहन शर्मा, कमलजीत और मनु कुमार को पुरस्कार प्रदान किये गये, जबकि चम्बा रूमाल प्रतियोगिता में दिनेश कुमारी, इंदू शर्मा व कमला चडढा विजयी रहीं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार उन लेखकों को, जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, को प्रतिमाह एक हजार रूपये पेंशन प्रदान कर रही है। सरकार ने

कलाकारों और लेखकों की पुरस्कार राशि को 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये, जबकि शिखर सम्मान 51,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया है।

शिमला दूरदर्शन में CBI की छापेमारी

शिमला/शैल। विवादों के लिए सुर्खियों में रहने वाले दूरदर्शन शिमला में सीबीआई व दूरदर्शन की विजीलेंस टीम ने छापेमारी कर ढेरों कागजातों की पड़ताल की है। सुबह 11 बजे से शुरू हुई ये पड़ताल शाम आठ बजे तक भी चलती रही है। जानकारी के मुताबिक मामला शिमला दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले नाटकों व धारवाहिकों की रायलिटी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दूरदर्शन में बड़े पैमाने पर हो रही वितीय अनियमितताओं का कच्चा चिटठा किसी ने सीबीआई व दूरदर्शन के दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेजा था।

इस कच्चे चिटठे को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई ने शिमला दूरदर्शन के कार्यालय में दबिश दे दी व कार्यालय के मुलाजिमों के पहचान चैक किए गए। स्टाफ को गेट पर रोका भी गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारीयों व कर्मचारीयों ने दूरदर्शन कार्यालय में सारा रिकार्ड छाना है। सीबीआई रेड के बारे में केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने भी पुष्टि की है। सीबीआई ने बहुत सा रिकार्ड अपने कब्जे में लिया। दूरदर्शन के अधिकारी इस रेड को रूटीन काम बता रही है। लेकिन सूत्र बताते है कि ये रेड अनियमितताओं के मामले से जुड़ी है। शिमला दूरदर्शन विवादों के लिए मशहूर रहा है। कैजुअल व पार्ट टाइम कर्मचारी यहां पर धरना प्रदर्शन कर चुके है। इसके अलावा कुछ लोग अदालत में भी जा चुके है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वीरभद्र प्रकरण में

सी बी आई और ई डी जांच के कुछ महत्वपूर्ण खुलासे

शिमला/शैल। सी बी आई ने पन्द्रह घण्टे वीरभद्र सिंह से पूछताछ की है। अभी ई डी में पूछताछ होना बाकि है क्योंकि ई डी में अभी तक कोई पेश ही नहीं हुआ है। पन्द्रह घण्टे की पूछताछ का आधार बनी जांच रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण खुलासे पाठकों के सामने रखे जा रहे हैं। यह खुलासे 23 मार्च के अटैचमैंट आदेश के हिस्से हैं।जो ई डी के संयुक्त निदेशक डा0 गिरीश बाली द्वारा जारी किया गया है।

1 That during the check period from 28.05.09 to 26.06.2012 shri Virbhadra Singh acquired assets disproportionate to his known source of income to the tune of Rs. 6,03,70,782/ - and further tried to justify the same in the name of agriculture income

2.During the course of assessment proceedings, huge cash deposits were noticed in Bank A/Cs No. 3889000100524815 & 03461000004301 maintained with Punjab National Bank and HDFC Bank both located at Sanjauli Shimla in the name of Shri Anand Chauhan. He claimed in his initial reply to the Income Tax department dated 22-11-2011 that cash deposits belonged to his joint family but later on changed his version by giving a copy of Memorandum of Understanding dated 15-06-2008 with Shri Virbhadra Singh (HUF) for management of ShriKhand Orchard at Damrali Rampur Bushar and explanation that cash deposits were from sale of agricultural produce sold on behalf of Shri Virbhadra Singh (HUF) The original M.O.U. was not produced for verification before Income Tax authorities and there were cuttings in the photo -copy furnished and also cuttings in the register of vendor who had issued the stamp paper.

3.Shri Anand Chauhan had been regularly depositing cash amounts in the said accounts and got LIC policies issued in the name of Shri Virbhadra Singh and his family members i.e. Smt. Prathiba Singh, Shri Vikramaditya Singh and Ms. Aprajita singh.

4. On 02-03-2012 Virbhadra Singh (HUF) filed revised returns of income for 3years and increased the agricultural income substantially from Rs 47.35 lacs to Rs 6.56 crores.

5.According to the Income Tax investigation the contention of Shri Anand chauhan and Virbhadra singh (HUF) to justify the sudden increase in agricultural income was that :-

(**a**) Shrikhand orchard consisted of about 3500/- trees . The production of one tree was approximately 8-10 boxes. Therefore Shrikhand orchard was capable of producing about 35000 boxes and same could easily be sold for Rs. 2.5 -3.0 cr.

6. The I -Tax authorities were of the view that since it is the claim of suspected persons that approx. 35000 number of boxes of apples were produced and transported mostly through tipper vehicles, these small vehicles could carry only between 100-250 boxes in tippers and much lesser boxes in other small vehicles. Hence about 200 to 250 trips will be required to transport 35000 boxes. The suspicion of I-Tax authorities was found true when not even a single entry of these vehicles found their mention in the Govt. Records. Thus I-Tax authorities were of firm conclusion that no such agriculture produce was ever transported from Rampur to Parwanoo.

. But surprisingly , the LIC policies purchased through Shri Anand chauhan on the behalf of the members of the HUF after signing original LIC application forms from 2008-09 onwards made it amply clear that Shri Virbhadra Singh as Karta of HUF, was in full knowledge about the investments made in purchase of LIC policies much before settlement of accounts .

8. Credible Information was received from office of Life Insurance Corporation , sanjauli Branch, Shimla vide letters dated 12.01.2016 , 29.01.2016, 13.02.2016 and 18.02.2016 which confirmed that 19 policies were purchased in the names of Shri. Virbhadra Singh and his family members. The Life Insurance policies of life Insurance Corporation of India through sanjauli Branch Shimla H.P. had been purchased from 2007 to 2010 (one policy out of 19 relates to the year 1994) mostly in cash in the names of Sh. Virbhadra singh S/o Late Sh. Padam singh R/o Holly Lodge. Jakhoo. Shimla HP Smt. Pratibha singh W/o Shri Virbhadra singh R/ o Holly Lodge, Jakhoo Shimla H.P. and Ms. Aprajita singh D/o Sh. Virbhadra singh R/o Holly Lodge, Jakhoo Shimla HP. Out of these policies, only 4 policies are in force and majority of them were enchashed A summary of the information provided by LIC vide their letters dated 12.01.2016 , 29.01.2016 13.02.2016, 18.02.2016 ,06.02.2016 ,24,02.2016, 25-02-2016 and details of transactions from bank account of Sh. Virbhadra singh his family members shows how the policies were obtained and where the redemption was used.

9. AND WHEREAS the investigation revealed that most of the LIC policies were purchased through one Sh. Anand chauhan. One policy bearings number 153596174 in the name of Shri Vikramaditya singh was purchased from account of Ms. Kanupriya Rathore with PNB sanjauli bearing NO. 1488001500000881 in 2010. Three LIC polices were purchased from the two separate accounts of Shri Meghraj Sharma bearing number SB- 20016 with Punjab and Sind Bank, Sanjauli and A/c No. 3889001300000819 with PNB Sanjauli. All the cash deposits against which the policies were purchased were deposits by shir Anand Chauhan in his bank account and in the accounts of Shri Meghraj Sharma and Ms. Kanupriya Rathore.

10. To check the veracity of claim of substantial increase shown in the sales of apples by Anand Chauhan enquires were made with the other alleged contractor Shri Bishambar Dass. The contract for Shrikhand Orchards in year 2008-09 was with one Shri Bishamber Dass S/o Shri Durga Dass R/o Village P.o Danda, Tehsil Rampur Distt. Shimla (HP) He in his statement dated 15.01.2016.He stated that he never met Shri Anand chauhan or heard abouthim in Shrikhand orchard.

11.(IV) Approximate yield of Apple in 105 Bigha orchard situated in District Shimla based on the working done replied earlier by Director of Horticulture was as under:-

Sr. No	Year	Approximate Yield of apple in 105 bighas orchard	Number of expected boxes of Apples (calculations as per Assessment order of IT authorities)
1.	2008-09	112.812 MT	5500
2.	2009-10	55.860 MT	2700
3	2010-11	191.604 MT	9300

12. Statement of Sh. Bhanu Sharma S/o Late R.N Sharma Secretary APMC Solan was recorded on 08.02.2016 who stated that.:-

(i) TheMandi at Parwanoo started about 28 years back and it stopped functioning after 4-5 years of its operation after which Mandi started functioning from july 2009 onwards till date.

(ii) That form R was a grower parcha which is given by the commission agent to the grower of the crop mentioning the Rate Quantiy total amount of the crop etc.

(iii)That Form Q is a bill which is given to the buyer by the commissions agent mentioning the commission which is 6% out of which 1% is to be deposited as Market Fees to the APMC.

However no required documents as mandated by APMC were Submitted by Anand chauhan during the course of investigation.

13. The records of the Directorate of Transport 04-03-2016 revealed that the (vehicle numbers) as obtained from records of CBI provided in the sale vouchers issued to Shrikhand Orchard by Chunni lal Chauhan were not in existence. The enquiry of vehicles conducted by the I.T department also brought out the fact that the vehicles were not of the type and make capable of transporting the apples.

14. He admitted that no overwriting or cutting is allowed in the register maintained for stamp paper. But at the same time he agreed that he made entries at Serial No 1284 and 1287 of the register and the stamp papers were allegedly sold to Shri Anand chauhan and there was overwriting on both the entries of stamp papers on the Register.

15. Above facts indicate that the stamp paper with entry no.1248 of the stamp vendor register was used by Laiq Ram in the UCO Bank the Same entry of the stamp vendor registered has been made on stamp paper used by Virbhadra singh in agreement between him and Anand chauhan. The above enquiry clearly shows that a fabricated agreement was signed between Sh.Virbhadra singh and Sh. Anand Chauhan.

16. Further he claimed that all the payments in cash were made from his office only except one crore rupees which was made by buyers to Anand chauhan through him for which he made 13 general entries that thses payments were made at his office by buyers directly. On being asked about providing details regarding the highest amounts of cash payments to Anand chauhan he denied remembering the same

17. As his statement of payment of one crore was contradictory to the field enquiries done from the buyers of apples he was quizzed about reply received from 6 firms out of 13 named by him i.e. RS Anwar Sons Chennai P.R. Ganapti Chennai, EDS fruit Chennai R. Syed Omar. Diamond Fruit Company, Bangalore, Patambi Fruit company Kereala which denied making any cash payment to him or through him whereas other were either not existing at the given address or could not be located . He was evasive and said he did not know why they are saying so.

18. Meghraj Sharma states that 3 LIC Policies were issued in the name od Smt. Pratibha Singh Sh. Vakramaditya singh and Ms. Aprajitas Kumari bearing No. 153596173, 153234332 and 153234335 vide cheque No. 112921 of Rs. 50,00,000/- from his account in Punjab National Bank Sanjauli in February 2010 Two policies of Rs. 10,00,000/- each was issued vide Cheque No. 21570 of Rs. 20,00,000/- issued from his account with Punjab and sind Bank sanjauli Branch.

B) That the amounts in his bank accounts were deposited in cash by sh. Anand chauhan who was an LIC agent '

19. Shri Dinesh Sood who has been reportedly handling transport from Shrikhand orchard was summoned on 22-03-2016 and he stated that in the F.Y. 2008 -09 , 09-2010 & 2011-2012 he had given his vehicle No. HP 63 - 1568 to Ram Asray Thakur .

(IV) That Ram Ashrey Thakur used to utilize the said truck for transporting fertilizer, stones etc.

(V) That he did not know shri Anand chauhan and shri Chunni Lal Chauhan.

20. That the agreement with Bishamber Dass forged and fabricated on a back date as revealed by enquiry regarding stamp paper being dispatched by the security press on a date later than the signing of the said agreement meaning thereby that there was no genuine agricultural income.

21. Anand chauhan knew that he had to deposit cheque with LIC then why he would take the risk of carrying cash all the way from Parwanoo to Shimla and then keep it with him for days. He has deposited cash whenever required for obtaining LIC policy. Therefore his assertion that he took cash from sale of fruits appears to be a ploy to cover up proceeds of crime and to project the same as untaunted property.